मुख्यमंत्री भजनलाल ने सीमा प्रहरियों से संवाद किया व तिरंगा यात्रा में शामिल हुए

स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने अनूपगढ़ और सादुल शहर का दौरा किया

श्रीगंगानगर/जयपुर, (निसं), 14 अगस्त। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अनूपगढ़ के 2 बीएनएम पहुंचकर, बीएसएफ चौकी की बॉर्डर आउटपोस्ट एवं सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा जवानों से संवाद किया। सादुलशहर में देशभक्ति के नारों की गूंज के बीच हाथ में तिरंगा लेकर मुख्यमंत्री अंबेडकर सर्किल से अरूट चौक तक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए।

जवानों के साथ संवाद में उन्होंने कहा कि 'जीवन पर्यन्त कर्तव्य' के ध्येय

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीएसएफ की बॉर्डर आउट पोस्ट तथा सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने चूनावढ़ में मिल्क चिलिंग प्लांट की घोषणा की तथा सादुल शहर में उप जिला चिकित्सालय के नवीन भवन का शिलांयास किया।**

वाक्य को सार्थक करते हुए बीएसएफ त्याग, शौर्य, साहस एवं समर्पण से देश की सुरक्षा और संप्रभुता को और मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीएसएफ के जवानों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं तथा कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया गया है। इससे सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी नई गति मिली है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को सादुलशहर में अंबेडकर सर्किल से अरूट चौक तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने 23वीं वाहिनी बीएसएफ परिसर में पौधारोपण भी किया।

सादुलपुर में जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्राओं में नागरिकों का जोश और जुनून इस बात का प्रमाण है कि तिरंगा हमारे दिलों में बसता है। साथ ही, यह हमारे गौरव और राष्ट्रीय चेतना की विरासत और पहचान है, जो हमें स्वतंत्रता और उससे जुड़े इतिहास को याद दिलाता है। जनसभा में मुख्यमंत्री ने सादुलशहर के चूनावढ़ में मिल्क चिलिंग प्लांट की घोषणा की। उन्होंने सादुलशहर में ही राजकीय उप जिला चिकित्सालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया। तिरंगा यात्रा में केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, विधायक गुरवीर सिंह सहित, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद थे।

राष्ट्रपति के संबोधन से पहले वंदे मातरम बजाया गया

नई दिल्ली, 14 अगस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को विद्यार्थियों को देश के भविष्य का निर्माता बताते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं को पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए व्यापक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी

- **ऐसा पहली बार हुआ है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के भाषण से पहले वंदे मातरम बजाया गया और उसके बाद जन गण मन बजाया गया।**

तरह अंकुश लगे और युवाओं को अपनी प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ ने का निष्पक्ष अवसर मिले।

राष्ट्रपति ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में 2047 तक विकसित भारत के निर्माण, युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण, गरीबों और वंचितों के कल्याण, डिजिटल एवं भौतिक बुनियादी ढ ांचे, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत देश की विकास यात्रा के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासियों की एकजुटता, परिश्रम और संकल्प शक्ति से राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

'मामला मेरे और छात्रों के बीच है, बीसीआई को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं'

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नालसर युनिवर्सिटी (नैशनल लॉ युनिवर्सिटी) के छात्रों से जुड़े विवाद में बार काउन्सिल ऑफ इंडिया के हस्तक्षेप की आलोचना की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अगस्त। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के प्रस्ताव को लेकर हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों से जुड़े विवाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के हस्तक्षेप पर असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीसीआई की कार्रवाई को बिल्कुल अनुचित बताया और निर्देश दिया कि छात्रों या शिक्षकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि बीसीआई ने नालसर के 2026 के स्नातकों का अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण रोकने वाला अपना पत्र वापस ले लिया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, "स्वाभाविक रूप से, यह बिल्कुल अनुचित है। यह छात्रों और मेरे बीच बातचीत का मामला है। वे इस मुद्दे को उठाने वाले कौन होते हैं? यह पूरी तरह अनुचित है। अपने छात्र जीवन में, मैं भी छात्र गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा हूं। अगर मान भी लें कि वे गलत हैं, तब भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है। बीसीआई का इसमें कोई काम नहीं है।"

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों द्वारा व्यक्त

- **सीजेआई की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमालया बागची एवं वी मोहना शामिल थे, ने बी.सी.आई. को निर्देश दिया कि छात्रों पर कोई दंडात्मक कार्यवाही न की जाए। साथ ही बीसीआई को जवाबी शपथ पत्र देने को भी कहा।**
- **ज्ञातव्य है कि नालसर युनिवर्सिटी के छात्रों ने दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत को नहीं बुलाने का आग्रह किया था, इस पर बीसीआई ने सभी छात्रों के बार काउन्सिल में पंजीकरण पर रोक लगा दी थी, लेकिन भारी विरोध के बाद बीसीआई ने यह आदेश वापस ले लिया।**

किए गए मतभेद उनके पेशेवर करियर में बाधा नहीं बनने चाहिए। उन्होंने कहा, "युवा अवस्था में अगर कोई गलत बात कहता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे विरोध करने का अधिकार नहीं है। कृपया सभी छात्रों से कहें कि वे पंजीकरण कराएं, सुप्रीम कोर्ट बार में शामिल हों। हम उन्हें कानूनी सहायता के मामलों के लिए पैनल में शामिल करेंगे और उन्हें कानूनी सहायता का काम करने दें। उन सभी लोगों को यही उचित जवाब होगा, जिन्होंने उनके पेशेवर करियर में बाधा डालने की कोशिश की।"

ये टिप्पणियां तब आईं, जब वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख किया और सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय के भीतर चल रहे मामले में बीसीआई को हस्तक्षेप करने का अधिकार कैसे है।

परमेश्वर ने कहा, विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, इससे बीसीआई का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने केरल से बीसीआई के एक सदस्य का भी जिक्र किया, तथा, उनके अनुसार, बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा जारी किए गए पत्र की उन्हें जानकारी नहीं थी। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि बीसीआई ने गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को दो पत्र जारी किए थे। इनमें एक शाम 5 बजे और दूसरा शाम 7 बजे जारी किया गया था।

सुनवाई के दौरान बीसीआई की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि विवादित पत्र अब वापस ले लिया गया है।

इसके बावजूद, कोर्ट ने बीसीआई को नोटिस जारी किया, जिसे उसके वकील ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने बीसीआई से दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।

पूर्व टीएमसी विधायक को भीड़ ने थाने के बाहर पीटा

कोलकाता, 14 अगस्त। कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में हुए दुष्कर्म-हत्या काण्ड की पीड़िता की कथित जल्दबाजी में अंत्येष्टि का मामला फिर गरमा गया है। मामले में गिरफ्तार पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष पर शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले में भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद लोगों ने उन्हें लात-घूंसों से पीटा तथा जूते, अंडे और कीचड़ भी फेंका। घोष को एक दिन पहले ओडिशा से गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन विधायक के तौर पर पीड़िता के शव की जल्दबाजी में अंत्येष्टि कराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। जानकारी के अनुसार, घोष को खड़दह पुलिस थाने से बैरकपुर उपमंडलीय अदालत ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बाहर जमा भीड़ ने उन्हें घेर लिया।

दिल्ली हाई कोर्ट सहित 5 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी

पाँचों स्थानों की गहन जाँच-पड़ताल की जा रही है, हालांकि, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, पर निगरानी बढ़ा दी गई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। हाई कोर्ट प्रशासन ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है और मामले की आगे जांच की जा रही है।

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से एक दिन पहले, दिल्ली हाई कोर्ट समेत, राष्ट्रीय राजधानी में पांच स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

डीएफएस के अनुसार, जामनगर हाउस, झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, साकेत स्थित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल-3 और दिल्ली कैंट स्थित एसडीएम कार्यालय को लेकर बम विस्फोट की धमकी वाले फोन कॉल प्राप्त हुए।

पांचों स्थानों पर दमकल की गाड़ियां भेजी गईं। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि अब तक की गई जांच में कोई संदिग्ध वस्तु या सामग्री नहीं मिली है।

ताजा धमकियां दिल्ली के मेयर कार्यालय को 3 अगस्त को मिले उस ईमेल के कुछ दिनों बाद आई हैं, जिसमें 15 अगस्त को लाल किले में कई बम विस्फोट किए जाने की चेतावनी दी गई थी। इस ईमेल के बाद दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने ऐतिहासिक लाल किले के आसपास व्यापक सुरक्षा अभियान शुरू किया था।

मेयर कार्यालय को धमकी मिलने के बाद, उसने दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को इसकी जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि इसके तुरंत बाद, लाल किले में पुलिसकर्मियों, बम निरोधक दस्तों और अन्य सुरक्षा इकाइयों को तैनात किया गया। उन्होंने

- **दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा, जाम नगर हाउस, झंडेवालान फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लैक्स, साकेत का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 और दिल्ली कैंट के एसडीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।**
- **इससे पहले 3 अगस्त को भी धमकी भरा ई-मेल आया था। दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों ने बम निरोधक दस्तों व अन्य सुरक्षा इकाइयों को तैनात किया है।**

परिसर की व्यापक तलाशी लेने के साथ-साथ, पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, इसके बाद इलाके की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई तथा मामले की जांच शुरू की गई।

इससे पहले 11 जुलाई को लाल किले को निशाना बनाकर दी गई एक अलग बम धमकी के बाद भी बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाया गया था। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले तथा उसके आसपास के इलाके की विस्तृत तलाशी ली थी। बाद में इस धमकी को फर्ज़ी पाया गया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, जुलाई में मिली धमकी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में किए गए एक फोन कॉल के जरिए दी गई थी। कॉल करने वाले ने कथित तौर पर ऐतिहासिक लाल किले को बम से उड़ाने की बात कही थी। मुंबई पुलिस ने तत्काल यह सूचना दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद उत्तर जिला पुलिस को सतर्क किया गया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई।

गहन तलाशी लेने के बाद पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली और धमकी को फर्ज़ी घोषित कर दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और इसके मद्देनज़र राजधानी में व्यापक यातायात एवं आवागमन प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।

ब्रिक्स समिट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत, इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बैठक में प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। सम्मेलन में सहयोग, व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह यात्रा क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर भारत और ईरान के बीच बातचीत को और मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

भारत इस वर्ष "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" विषय के तहत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने 78 वीरता पुरस्कार घोषित किए

नई दिल्ली, 14 अगस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों

- **13 वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे।**

को मंजूरी दी, जिनमें 13 मरणोपरांत दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों में नौ कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, पांच बार टू सेना मेडल (वीरता) और 36 सेना मेडल (वीरता) शामिल हैं। कीर्ति चक्र, अशोक चक्र के बाद भारत का शांति के समय दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। शौर्य चक्र शांति के समय दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है।

रेलवे ने यात्रियों के साथ 168 करोड़ रूपए का फर्ज़ीवाड़ा किया

भारत के कंट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे ने यात्रियों से उन ट्रेनों में भी सुपर फास्ट सरचार्ज वसूला जो निर्धारित गतिमानकों को पूरा नहीं करती हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अगस्त। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया-सीएजी) की एक कड़ी ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारतीय रेलवे ने उन ट्रेनों में भी सुपरफास्ट सरचार्ज वसूला, जो निर्धारित गति मानकों को पूरा नहीं करती थीं। इस तरह रेलवे ने यात्रियों से करीब 168 करोड़ की अतिरिक्त राशि वसूल की।

सीएजी की नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, यह अनियमित वसूली अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच हुई और इसमें190 से अधिक ट्रेनें शामिल थीं।

रेलवे के नियमों के मुताबिक, किसी ट्रेन को सुपरफास्ट ट्रेन की श्रेणी में रखने और उस पर सुपरफास्ट सरचार्ज लगाने के लिए उसकी औसत गति अप और डाउन- दोनों दिशाओं में कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए।

औसत गति की गणना ट्रेन द्वारा तय की गई अंतिम स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक की दूरी और यात्रा में लगे कुल समय के आधार पर की जाती है।

रेलवे द्वारा इस विसंगति को स्वीकार किए जाने के बावजूद, सीएजी को हैरानी हुई कि ट्रेनों में सुपरफास्ट सरचार्ज की वसूली जारी रही।

- **सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, यह वसूली अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच 190 ट्रेनों में की गई। सीएजी ने हैरानी जताई कि रेलवे ने इस गड़बड़ी को स्वीकार किया, पर सुपरफास्ट सरचार्ज की वसूली बंद नहीं की।**
- **सीएजी ने बताया, 190 ट्रेनों में से 100 ट्रेनें सुपरफास्ट के मानक को पूरा नहीं कर रही थीं, फिर भी इनके यात्रियों से सुपरफास्ट सरचार्ज वसूला गया।**

सीएजी के अनुसार, अगस्त 2024 में यह मामला रेलवे के समक्ष उठाया गया था। इसके बाद रेलवे ने ऑडिट की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए ऑडिटर को बताया कि सुधारात्मक कदमों पर विचार किया जा रहा है।

हालांकि, "इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम" से प्राप्त आंकड़ों की बाद में की गई जाँच में सामने आया कि ऑडिट में चिन्हित 190 ट्रेनों में से100 ट्रेनें मार्च 2026 तक भी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित सीमा से कम गति पर चल रही थीं।

सीएजी ने कहा कि इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों से इसके बावजूद सुपरफास्ट सरचार्ज वसूला जाता रहा, जबकि नवंबर 2025 में रेल मंत्रालय ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए थे।

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, सुपरफास्ट सरचार्ज की लगातार वसूली से संकेत मिलता है कि संबंधित रेलवे ज़ोनों द्वारा मंत्रालय के निर्देशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया।

ऑडिटर ने रेलवे से ट्रेनों के समय-सारिणी की समीक्षा और उसमें आवश्यक संशोधन करने को कहा है, ताकि सुपरफास्ट ट्रेन का दर्जा उसकी वास्तविक परिचालन गति के अनुरूप हो।

सीएजी ने सिफारिश की है कि केवल निर्धारित गति मानकों को पूरा करने वाली ट्रेनों को ही सुपरफास्ट श्रेणी में रखा जाए और उनसे अतिरिक्त सुपरफास्ट सरचार्ज वसूला जाए।

इन निष्कर्षों ने रेलवे की किराया निर्धारण व्यवस्था को लागू करने के तरीके और यह सुनिश्चित करने की प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि यात्रियों से अतिरिक्त किराया तभी लिया जाए, जब संबंधित ट्रेन निर्धारित सेवा मानकों को वास्तव में पूरा करती हो।

बैंकाक हवाई अड्डे पर 200 भारतीय फंसे

नई दिल्ली, 14 अगस्त। थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक में एयर इंडिया की फ्लाइट से भारत लौट रहे करीब 200 यात्री लंबे इंतजार में फंस गए हैं। यात्रियों के अनुसार, फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद पहले उन्हें विमान में बैठाए रखा गया, फिर एयरपोर्ट से होटल भेजा गया। अगले दिन दोबारा एयरपोर्ट बुलाया गया, लेकिन उड़ान का समय लगातार बदलता रहा।

यात्रियों का कहना है कि बैंकॉक एयरपोर्ट पर कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है।

कभी फ्लाइट को दो घंटे बाद उड़ाने की बात कही जाती है तो कभी चार घंटे का नया समय बताया जाता है। इस वजह से यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ ती जा रही है। कुछ यात्रियों का आरोप है कि एयरलाइन की ओर से उन्हें लगातार सिर्फ तकनीकी समस्या की जानकारी दी जा रही है जबकि दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई।

'चीन ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहले पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल और विभिन्न सामुदायिक संगठनों की एक तथ्य-जांच टीम (फैक्ट फाइन्डिंग टीम) ने भी उठाया था।

सरकार और सुरक्षा प्रतिष्ठान ने नई घुसपैठ के मुख्य आरोपों को खारिज कर दिया है। भारतीय सेना ने ताक्सिंग क्षेत्र में नए चीनी शिविर बनाए जाने और हाल में चीनी सैनिकों के प्रवेश की खबरों को गलत और निराधार बताया है।

मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकन जहाजों के नाविकों की मानसिक स्थिति अति गंभीर

कुछ नाविकों ने तो समुद्र में कूद कर आत्महत्या तक करने की कोशिश की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अगस्त। अमेरिका ने अपने प्रशांत क्षेत्र में तैनात विमानवाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन का रुख मध्य-पूर्व की ओर कर दिया है। यह घटनाक्रम लंबे समय से समुद्र में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और आपूर्ति संबंधी समस्याओं की खबरों के बीच सामने आया है। अब तक अब्राहम लिंकन ईरान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध अभियान में सहायता कर रहा था।

नौसेना के एक बयान के अनुसार, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन पिछले सप्ताह वियतनाम के दा नांग बंदरगाह से रवाना हुआ था। इसके बाद यह विमानवाहक पोत एक क्रूज़र और एक विध्वंसक पोत के साथ सिंगापुर स्ट्रेट से गुजरते हुए देखा गया।

एसोसिएटेड प्रेस ने नौसेना के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि जॉर्ज वॉशिंगटन मलक्का स्ट्रेट में था, जो प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ता है। अमेरिका ने इस विमानवाहक पोत को हिंद महासागर की ओर बढ़ने के लिए निर्धारित कर दिया है।

यह घटनाक्रम वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि मध्य-पूर्व में फिलहाल तैनात दो विमानवाहक पोतों में से एक अब्राहम लिंकन की जगह लेगा।

- **यही वजह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में होर्मुज़ में 260 दिनों से तैनात युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को तैनात करने का निर्णय लिया है।**
- **युद्ध पोत लिंकन पर मौजूद चालक दल और नौ सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अमेरिकन सांसदों व सैनिकों के परिवारों ने गंभीर चिंता जताई है।**
- **रिपोर्ट से पता चला है कि जहाज पर बुनियादी सुविधाओं, भोजन, पानी, शौचालय आदि में भारी कमी आई है तथा यहाँ डाक सेवा भी बाधित है, हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने इसे गलत तरीके से पेश खबर बताया।**

लिंकन पर तैनात सैनिकों के मनोबल को लेकर चिंता ऐसे समय सामने आई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका का होर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण है और वह इसे अपने नियंत्रण में बनाए रखेगा।

आमतौर पर नौसेना की तैनाती छह से नौ महीने तक होती है, लेकिन युद्ध के समय इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन लिंकन 260 दिनों से समुद्र में है, जो आधुनिक इतिहास में किसी विमानवाहक पोत की सबसे लंबी तैनातियों में से एक है।

जहाज पर तैनात सैनिकों के बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के संकट को लेकर, सैनिकों के परिवारों और अमेरिकी सांसदों ने चिंता जताई है। रिपोर्टों के मुताबिक, कई सैन्यकर्मियों ने जहाज से समुद्र में कूदने की कोशिश तक की है।

लिंकन को मूल रूप से 21 नवंबर 2025 को सैन डिएगो से रवाना किया गया था और यह फरवरी 2026 में ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने से पहले जनवरी 2026 में मध्य-पूर्व पहुंचा था।

अमेरिकी नौसेना ने स्वीकार किया कि संघर्ष के कारण ऐसा अत्यधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण पैदा हो गया, जहां मध्य-पूर्व में पारंपरिक आपूर्ति केन्द्र युद्धक गतिविधियों के कारण बाधित हो गए। इसके चलते विमानवाहक पोत पर जरूरी सामान की कमी और डाक व्यवस्था प्रभावित हुई।

नौसेना ने एक बयान में कहा, नेतृत्व ने मिशन के लिए जरूरी आपूर्ति को प्राथमिकता दी-सबसे पहले भोजन, फिर स्वच्छता संबंधी सामान और उसके बाद डाक। नौसेना ने यह भी आश्वासन दिया कि जहाज पर मौजूद नाविकों को अब साफ पानी और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के विकल्प उपलब्ध हैं।

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने लिंकन पर खराब परिस्थितियों की खबरों को खारिज करते हुए उन्हें "पूरी तरह गलत तरीके से पेश की गई खबर" बताया।

पनामा यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हर जहाज, हर चालक दल और हर कप्तान को हर समय वह सब कुछ मिले, जो हम उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। कुछ तैनातियां दूसरों से लंबी होती हैं और मैं उन नाविकों के प्रति किसी से भी अधिक सम्मान और आभार रखता हूं। वे खुले समुद्र में कठिन परिस्थितियों में, कम बंदरगाह पड़ावों के साथ जो काम कर रहे हैं, वह अविश्वसनीय है।

उनकी यह टिप्पणी दो सैन्य मामलों पर केन्द्रित मीडिया संस्थानों-नेवी टाइम्स और स्टार्स एंड स्ट्राइप्स की उन रिपोर्टों के बाद आई, जिनमें 5,000 सैनिकों वाले इस विमानवाहक पोत पर आत्महत्या के प्रयासों और गिरते मनोबल का उल्लेख किया गया था। लिंकन नवंबर 2025 से लगातार समुद्र में तैनात है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908